नव भारत, भोपाल
3 FEB 2010

बुंदेलखंड का विकास

मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच बंटा हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र में केंद्र की आर्थिक व योजना प्रारूप की मदद से विकास कार्य चल रहे हैं. केंद्र द्वारा अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को उसके हिस्से के 6 बुंदेलखंडी जिलों- दतिया, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ व सागर के लिये 3760 करोड़ रुपये आवंटित हुये हैं उनमें से बाकी 2160 करोड़ रुपये भी मिल गए. जिसे योजनाओं पर अगले तीन वर्षों में खर्च किया जाना है. विकास का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि संरचना हो तो रचना स्वयं हो जाती है. सभ्यता के विकास में नगर वहीं बसे जहां नदियां और जल संसाधन थे. जमीन, जल व ऊर्जा प्रमुख प्राकृतिक श्रोत हैं, जिन पर आधुनिक ज्ञान, विज्ञान व तकनीक से सड़क, बिजली से उन्हें विकसित कर विकास किया जा सकता है.

बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या वहां वर्षा की कमी और लगातार सूखे की स्थिति में फसल न होने से अकाल है. जिससे बुंदेलखंड में रोजगार के लिये सबसे अधिक जनसंख्या का पलायन होता है. पिछले 4 सालों में यहां 16 से 60 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है. बुंदेलखंड की 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और इनमें 60 प्रतिशत छोटे किसान हैं. मध्य प्रदेश वाले भाग में आबादी का घनत्व 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. सिंचाई के अभाव में पूरा क्षेत्र वर्षा के पानी पर निर्भर रहता है.

इन परिस्थितियों की दृष्टि से केंद्र ने बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि के विकास हेतु 'विशेष दर्जा' स्वीकृत किया है. यहां की योजनाओं में सिंचाई पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है. जल का अभाव यहां की सबसे बड़ी और भीषण समस्या है. इसलिये जल ग्रहण प्रबंधन (वाटर रोड मेनेजमेंट), पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि, सिंचाई व वनों का विकास इस क्षेत्र को दारिद्रय से उबार देगा. कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी ने इस क्षेत्र का सघन दौरा कर यहां की विपत्ति और जरूरतों को समझा.

उन्हीं की पहल पर केंद्र सरकार इस ओर सचेत हुई है और विशेष सहायता से यहां दोनों राज्यों आ रहे बुंदेलखंड में विकास का दौर तेजी से चल रहा है. इस सबके बावजूद बुंदेलखंड की जमीन काफी उपजाऊ है और सिंचाई मिलने से यहां कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हो सकती है.

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुंदेलखंड के प्रति सजग है. हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने यहां कामों की समीक्षा की है. जरूरत इस बात की है कि धन का उपयोग प्रशासन पर कम से कम योजनाओं के कामों पर ज्यादा से ज्यादा हो.